नव भारत

1934 से

इंदौर 65 वां वर्ष संस्करण

8 हिमाचल में अब भी जारी पांचाली प्रथा

5 बाढ़-बारिश से आधे हिंदुस्तान में तबाही

8 जहान हेमराजानी ने रचा इतिहास

9 एविएशन सेक्टर में 96,000 करोड़ निवेश : नायडू

भारत-यूके में फ्री ट्रेड डील

आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड बर्दाश्त नहीं : भारत-ब्रिटेन

लंदन/नयी दिल्ली 24 जुलाई. भारत और ब्रिटेन ने जोर देकर कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंडों की कोई जगह नहीं है और उग्रवादी विचारधारा वाली शक्तियों को लोकतांत्रिक आजादी का दुरूपयोग नहीं करने दिया जायेगा.

ब्रिटेन की आधिकारिक यात्रा पर आये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को लंदन में अपने समकक्ष कीर स्टार्मर के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद प्रेस वक्तव्य में कहा कि लोकतांत्रिक आजादी का दुरूपयोग कर लोकतंत्र को ही कमजोर करने वालों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए.

मोदी ने पहलगाम आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करने के लिए ब्रिटेन के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा, हम एकमत हैं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंडों का कोई स्थान नहीं

है. हम इस बात पर भी सहमत हैं कि उग्रवादी विचारधारा वाली शक्तियों को लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करने दिया जा सकता. लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का दुरूपयोग कर लोकतंत्र को ही कमजोर करने वालों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए. दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर को ऐतिहासिक बताते हुए उन्होंने कहा कि दोनों की अर्थव्यवस्थाओं को इससे बड़ा लाभ होगा. उन्होंने कहा, आज हमारे संबंधों में एक एतिहासिक दिन है. मुझे प्रसन्नता है कि कई वर्षों की मेहनत के बाद आज दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता संपन्न हुआ है. भारतीय टेक्सटाइल्स, फुटवियर, आभूषणों, समुद्री खाद्य उत्पादों और इंजीनियरिंग उत्पादों को ब्रिटेन के बाजार में बेहतर पहुंच मिलेगी. भारत के ऐग्रिकल्चर उत्पाद और प्रोसेस्ड फूड उद्योग के लिए ब्रिटिश मार्किट में नए अवसर बनेंगे.

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता देश के युवाओं और लघु, सूक्ष्म और मझोले उद्योगों के लिए खास तौर पर फायदेमंद रहेगा. उन्होंने कहा, भारत के युवाओं, किसानों, मछुआरों और एमएसएमई सेक्टर के लिए यह समझौता विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा. वहीं दूसरी ओर भारत के लोगों और इंडस्ट्री के लिए ब्रिटेन में बने उत्पाद जैसे मेडिकल डिवाइसेज़ और एयरोस्पेस कलपुर्जे सुलभ और किफायती दरों पर उपलब्ध हो सकेंगे

मोदी ने कहा कि दोनों देश व्यापक सामरिक साझेदारी को नयी दिशा देने के लिए विजन 2035 पर भी बात करेंगे. उन्होंने कहा, अगले दशक में हमारी व्यापक सामरिक साझेदारी को नयी गति और ऊर्जा देने के लिए आज हम विजन 2035 पर भी बात करेंगे. यह टेक्नोलॉजी, डिफेंस, क्लाइमेट, एजुकेशन और पीपल-टू-पीपल कनेक्ट के क्षेत्रों में एक मजबूत, भरोसेमंद और महत्वाकांक्षी साझेदारी का रोडमैप होगा.

समझौते के प्रमुख बिंदु

1. भारत की जेनरिक दवाओं को यूके बाजार में शून्य शुल्क पर प्रवेश.
2. ब्रिटेन की चीन-डिपेंडेंसी में कमी का फायदा भारत को मिलेगा.
3. सर्जिकल उपकरण, ईसीजी मशीन, एक्स-रे सिस्टम, डायग्नोस्टिक मशीनों पर भी कोई शुल्क नहीं.
4. केमिकल सेक्टर को ज़बरदस्त लाभ मिलेगा .
5. यूके हर साल 35 .11 अरब डॉलर के रसायन आयात करता है.

सांसदों के व्यवहार से युवाओं में जा रहा है गलत संदेश

- सांसदों के व्यवहार से नाराज हुए लोस अध्यक्ष
- लोकसभा-राज्यसभा चौथे दिन भी नहीं हो सका काम

नयी दिल्ली,24 जुलाई. संसद के मॉनसून सत्र में विपक्षी सांसदों के लगातार हंगामे को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला नाराज हो गए. बिरला ने कांग्रेस सांसदों को फटकार लगाते हुए कहा कि देश की नयी पीढ़ी विपक्षी सांसदों के व्यवहार को देख रही है. सांसदों के व्यवहार से युवाओं में गलत संदेश जा रहा है. वहीं, राज्यसभा की कार्यवाही लगातार चौथे दिन भी विपक्षी हंगामे की भेंट चढ़ गई.

गुरुवार को विपक्षी सांसदों से अपील करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्नकाल में बहुत अहम मुद्दे उठाए जाते है. यह जनता के हित से जुड़ा हुआ है और विपक्ष को प्रश्नकाल जनहित में चलने देना चाहिए. क्योंकि कई सांसदों का कहना है कि प्रश्नकाल में सवाल बड़ी मुश्किल से आता है. लेकिन विपक्षी सांसदों का व्यवहार संसद के गरिमा के खिलाफ है. भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और विपक्षी सदस्यों को लोकतंत्र की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए.

लोकसभा अध्यक्ष ने सांसदों की ओर मुखातिब होते हुए कहा, चुनाव में लाखों लोगों ने आपको चुनकर भेजा है, सांसदों को यह ध्यान रखना चाहिए कि लोगों ने सांसदों को सदन के अंदर तख्तियां लेकर हंगामा करने के लिए नहीं भेजा है. वहीं राज्यसभा में भी विपक्षी सांसदों की ओर से अपील करने के बाद भी हंगामा जारी रहा और सदन की कार्यवाही को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा.

एक नजर में

एअर इंडिया की उड़ान में आई तकनीकी खराबी

नयी दिल्ली. बुधवार रात दिल्ली से मुंबई जा रही एअर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान संख्या आईएक्स-1163 को उड़ान भरने से ठीक पहले तकनीकी खराबी के चलते टेकऑफ रद्द करना पड़ा. यह उड़ान रात 9.20 बजे रवाना होनी थी, लेकिन कॉकपिट में उड़ान नियंत्रण स्क्रीन में गड़बड़ी आने के कारण पायलटों ने सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए विमान को रोक दिया.विमान में 160 से अधिक यात्री सवार थे. तकनीकी खामी के बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित विमान से उतारकर टर्मिनल पर वापस लाया गया.

मंडी में सड़क दुर्घटना में पांच की मौत, 25 घायल

मंडी. हिमाचल प्रदेश में मंडी जिले के सरकाघाट-जामनी-दुर्गापुर मार्ग पर मसेरन तलगारा के पास गुरुवार सुबह एक यात्री बस के गहरी खाई में गिर जाने से पांच यात्रियों की मौत हो गयी और 25 अन्य घायल हो गये. आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि दुर्घटना के समय बस में 35 यात्री सवार थे. मृतकों में तीन महिलायें भी शामिल हैं. स्थानीय पुलिस और ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को खाई से बाहर निकाला गया और सरकाघाट अस्पताल ले जाया गया. तीन घायलों की हालत गंभीर बतायी जा रही है और उन्हें बिलासपुर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रेफर कर दिया गया है. सूत्रों ने बताया कि बस जामनी से सरकाघाट की ओर आ रही थी. सरकाघाट-जामनी-दुर्गापुर मार्ग पर मसेरन तलगारा के पास बस अचानक अनियंत्रित होकर खाई में गिर गयी. दुर्घटना के बाद ही राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया गया.प्रवक्ता ने बताया कि दुर्घटना के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है.

66 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण

- कंपनी कमांडर समेत 2.1 करोड़ के हैं ईनामी
- बीजापुर में बंदूकें अब ख़ामोश हो रही हैं : साय

कांकेर, 24 जुलाई. छत्तीसगढ़ के चार जिलों बिजापुर कांकेर, नारायणपुर और सुकमा में गुरुवार को सुरक्षा बलों तथा पुलिस को तब बड़ी सफलता हाथ लगी जब 2.1 करोड़ रुपये के ईनामी कंपनी कमांडर सहित 66 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया.

समर्पण करने वाले माओवादियों ने नौ महिला नक्सली भी शामिल हैं. बीजापुर जिले में आज एक करोड़ 15 लाख

के 23 इनामी समेत 25 हार्डकोर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ट्वीट कर बीजापुर में 25 हार्डकोर नक्सलियों के आत्मसमर्पण पर कहा, बंदूकें अब ख़ामोश हो रही हैं और बीजापुर बदलाव की राह पर है.

बीजापुर जिले में एक करोड़ 15 लाख के 23 इनामी समेत 25 हार्डकोर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है. यह बदलाव कोई संयोग नहीं बल्कि हमारी सरकार की 'आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति 2025' और जनकल्याणकारी योजनाओं की व्यापक स्वीकार्यता का प्रमाण है. 'नियद नेल्लानार योजना' जैसी पहलों ने आदिवासी अंचलों में विश्वास की नींव रखी है.

सिर्फ एससी/एसटी वर्ग का होना ही अभियोजन का आधार नहीं : सुको

नयी दिल्ली, 23 जुलाई. उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि शिकायतकर्ता का केवल अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग का होना ही इससे संबंधित कड़े अधिनियम के तहत अभियोजन का आधार नहीं हो सकता. मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के 2014 के उस फैसले के खिलाफ कोंडे नागेश्वर राव की ओर से दायर अपील को खारिज करते हुए ये टिप्पणियां कीं. दोनों उच्च न्यायालयों के संबंधित फैसले में एससी/ एसटी से संबंधित विशेष कानून के तहत दो व्यक्तियों के खिलाफ शुरू की गई.

भागवत की 60 मुस्लिम धर्मगुरुओं संग बैठक

सांप्रदायिक सद्भाव के लिए अहम पहल, दिल्ली में हुई बातचीत

एक राष्ट्र, एक झंडा, एक राष्ट्रगान को बढ़ाने का उद्देश्य

नयी दिल्ली, 24 जुलाई. सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत ने दिल्ली के हरियाणा भवन में 60 मुस्लिम धर्मगुरुओं और बुद्धिजीवियों के साथ एक बैठक की.

इस बैठक में संघ के महासचिव दत्तात्रेय होसबाले, सह-महासचिव

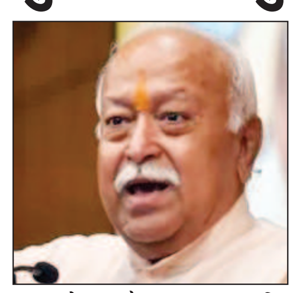

कृष्ण गोपाल के साथ-साथ वरिष्ठ पदाधिकारी राम लाल और इंद्रेश कुमार भी उपस्थित रहे. सूत्रों के अनुसार, अखिल भारतीय इमाम संगठन के प्रमुख उमर अहमद इलियासी सहित कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इस बैठक में भाग लिया. आरएसएस, अपने संबद्ध संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच (एमआरएम) के माध्यम से, मुस्लिम धर्मगुरुओं, विद्वानों और समुदाय की प्रमुख हस्तियों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ता रहा है. 2022 में, एमआरएम ने अल्पसंख्यक समुदाय के साथ जुड़ने और एक राष्ट्र, एक झंडा, एक राष्ट्रगान की अवधारणा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक राष्ट्रव्यापी अभियान की योजना की घोषणा की थी. मोहन भागवत ने 2022 के सितंबर में भी कई प्रमुख मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मुलाकात की थी, जिसका उद्देश्य भारत में धार्मिक समावेशिता को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा करना था. उस बैठक का लक्ष्य संघ के विचारों का प्रचार करना और समुदायों के बीच आपसी समझ को बढ़ावा देना था.

अनिल अंबानी के 40 ठिकानों पर ईडी छापे

- एडीए समूह की कंपनियों के कार्यालयों पर केंद्रित
- 3,000 करोड़ के अवैध डायवर्जन का मामला

मुंबई, 24 जुलाई. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने यस बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में देश भर में व्यापक तलाशी अभियान चलाया है जिसमें मुंबई के एक प्रमुख उद्योगपति से जुड़ी कई संपत्तियों को निशाना बनाया गया है.

दिल्ली और मुंबई की ईडी टीमों ने गुरुवार को एक साथ 40 स्थानों पर तलाशी ली, जिसमें उद्योगपति का निजी निवास भी शामिल है. ये

तलाशी अभियान रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह (एडीए समूह) के तहत कंपनियों के कार्यालयों पर केंद्रित था, जो एक बड़े धन शोधन जांच का हिस्सा है.

आधिकारिक सूत्रों ने पुष्टि की है कि यह कार्रवाई यस बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले की चल रही जाँच से जुड़ी हुई है, साथ ही उद्योगपति के रिलायंस एडीए समूह के अंतर्गत आने वाली कंपनियों से संबंधित अन्य वित्तीय जाँच से भी जुड़ी है.

तलाशी विशेष रूप से एडीए समूह की कंपनियों के कार्यालयों पर केंद्रित थी. यह कार्रवाई भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी), राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण , बैंक ऑफ बड़ौदा और दो अलग-अलग केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी (एफआईआर) सहित कई एजेंसियों से प्राप्त जानकारी पर आधारित थी.

उन्होंने बताया कि जांच का केंद्र 2017 और 2019 के बीच यस बैंक द्वारा स्वीकृत ऋणों में से लगभग 3,000 करोड़ रुपये के कथित अवैध डायवर्जन का मामला है.

> अधिकारियों को संदेह है कि यह धनराशि एडीए समूह की कंपनियों तक पहुँचने से पहले बैंक के प्रवर्तकों से जुड़ी संस्थाओं के माध्यम से भेजी गई थी. विशेष रूप से रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) ऋण वितरण में भारी उछाल के कारण जांच के दायरे में है, जो वित्त वर्ष 2018 में 3,742.6 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2019 में 8,670.8 करोड़ रुपये हो गया.

गुस्ताखी माफ

रणनीति | शिवराज सिंह चौहान और थावरचंद गहलोत का नाम चर्चा में शामिल

उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम पर मंथन शुरू

प्रवेश कुमार मिश्र

नयी दिल्ली, 24 जुलाई. पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद जल्द होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव को ध्यान में रखते हुए भाजपा व संघ के रणनीतिकारों ने संभावित उम्मीदवारों के नाम पर बहुस्तरीय विमर्श आरंभ कर दिया है. जिन संभावित उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हो रही है उसमें मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व केन्द्रीय मंत्री शिवराजसिंह चौहान और कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत का नाम प्रमुख रूप से शामिल है.

चर्चा है कि भाजपा व संघ के रणनीतिकार पूर्व के कड़वे अनुभवों

को ध्यान में रखते हुए दूसरी विचारधारा को छोड़कर राजनीतिक कारणों से भाजपा व संघ की विचारधारा को अपनाकर उच्च पद प्राप्त करने वाले नेताओं को महत्वपूर्ण संवैधानिक पद देने को तैयार नहीं हैं. संभवत: इसी वजह से कई वरिष्ठ नेताओं का नाम आरंभिक मानदंड के कारण ही इस दौड़ से बाहर हो गया है. हालांकि सूत्रों का दावा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विशेष पसंद व भाजपाई रणनीतिकारों के किसी विशेष राजनीतिक रणनीति के तहत इस पद की रेस में जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद व बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के नाम को संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट में शामिल रखा गया है. सूत्रों की मानें तो राजग के सहयोगी दलों की ओर से भी नाम प्रस्तावित किया गया है. जदयू कोटे से राज्यसभा के मौजूदा उपसभापति हरिवंश सिंह, केन्द्रीय राज्यमंत्री व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के पुत्र रामनाथ ठाकुर का नाम प्रस्तावित किया गया है जबकि कुछ लोग दलित चेहरे के तौर पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व केन्द्रीय मंत्री जीतन राम मांझी तथा आंध्र प्रदेश से संबंध रखने वाले किसी वरिष्ठ टीडीपी नेता का नाम भी लिया जा रहा है.

> सूत्र बता रहे हैं कि संघ किसी भी हाल में दूसरे दल या पूर्व में दूसरी विचारधारा के साथ रहने वाले संभावित नाम पर विचार करने के पक्ष में नहीं है. इसलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, कृषि मंत्री शिवराजसिंह चौहान, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, राज्यपाल थावरचंद गहलोत, उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, पूर्व सांसद रमा देवी, वरिष्ठ नेता ओम माथुर जैसे अनुभवी नेताओं के नाम पर विभिन्न दृष्टिकोणों से मंथन किया जा रहा है.

सत्यमेव जयते | मध्यप्रदेश शासन | प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना | 25 2000-2025 | इफको-टोकियो जनरल इंश्योरेंस मुस्कुराते रहो

भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रायोजित

इफको-टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

द्वारा क्रियान्वित अधिसूचित खरीफ 2025 की फसलों के लिये

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)

UIN: IRDAN106RP0001V01201617

अधिसूचित जिला-उज्जैन

योजना का उद्देश्य

PMFBY का उद्देश्य सभी क्षेत्रों में अप्रत्याशित घटनाओं के उत्पन्न फसल हानि/क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करके कृषि क्षेत्र में स्थाई उत्पादन का समर्थन करना है।

बीमा के लिए पात्र कृषक

सभी कृषक (स्वयं/बटाई/पट्टे पर खेती करने वाले) जो अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल की खेती कर रहे हैं।

पात्रता

ऋणी कृषकों के लिए : कृषक जो योजना में शामिल नहीं होना चाहते, उन्हे भारत सरकार द्वारा जारी चयन प्रपत्रानुसार हस्ताक्षरित घोषणा पत्र खरीफ के लिए बीमा कराने की अंतिम तिथि से 7 दिन पूर्व संबंधित वित्तीय संस्थान में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा, अन्यथा संबंधित बैंक द्वारा संबंधित मौसम के लिए स्वीकृत/ नवीनीकृत की गई कृषि ऋण को अनिवार्य रूप से बीमाकृत किया जायेगा।

अऋणी कृषकों के लिए: कृषक अपनी फसल का बीमा प्रस्ताव पत्र पूर्ण रूप से भरकर आवश्यक दस्तावेज नवीनतम भू अधिकार पुस्तिका, बुआई प्रमाण-पत्र, बैंक पास बुक, आधार कार्ड की कॉपी एवं प्रीमियम सहित निकटतम व्यावसायिक, सहकारी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सामान्य सेवा केन्द्र (CSC), भारत सरकार की वेबसाइट www.pmfby.gov.in अथवा फसल बीमा ऐप के द्वारा भी करवा सकते है।

बीमा हेतु अधिसूचित खरीफ फसलें

सोयाबीन व उड़द

कृषक द्वारा देय प्रीमियम दर

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमित राशि का 2%

बीमा कराने की अन्तिम तिथि

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना - 31 जुलाई, 2025

फसल बीमा सप्ताह 1-7 जुलाई, 2025 पीएमएफबीवाई

आवरित जोखिम

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत

अधिसूचित बीमा इकाई के आधार पर

क) प्रतिकूल मौसम के कारण 75% से अधिक क्षेत्र में बुआई न कर पाने/असफल बुआई की स्थिति में क्षतिपूर्ति का प्रावधान।

ख) फसल कटाई प्रयोग के आधार पर प्राप्त उपज में थ्रेशोल्ड उपज से कम आने पर क्षतिपूर्ति।

ग) फसल मौसम के मध्य में, यदि प्राकृतिक आपदाओं के कारण अनुमानित वास्तविक उपज, थ्रेशोल्ड उपज से 50% से कम रहने की संभावना की स्थिति में तत्काल क्षतिपूर्ति एवं ऑन अकाउन्ट पेमेन्ट का प्रावधान।

व्यक्तिगत खेत के आधार पर (स्थानिक आपदा)

क) ओलावृष्टि, भू-स्खलन, बादल फटना, जलभराव एवं आकाशीय बिजली से उत्पन्न आग के कारण खड़ी फसल को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति।

ख) फसल कटाई उपरांत नुकसान-फसल कटाई से अधिकतम 14 दिनों की अवधि तक खेत में फसल कटी या फैली हुई स्थिति में चक्रवात/चक्रवातीय वर्षा, ओलावृष्टि एवं बेमौसम बारिश के कारण हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति।

कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाईन 14447 (टोल फ्री)

पीएमएफबीवाई के लिए व्हाट्सएप्प पर हमसे जुड़ें +91-7065514447

★ स्थानिक आपदा हेतु जोखिम की सूचना कृषक द्वारा 72 घण्टे के भीतर कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाईन 14447 या कृषि कार्यालय/बैंक/फसल बीमा (PMFBY) ऐप पर अनिवार्य रूप से देनी होगी।

★ बीमित कृषकों द्वारा बीमित फसल के नाम में परिवर्तन की सूचना कट-ऑफ डेट से 2 दिन पहले बैंक शाखा, बीमा मध्यस्थ, फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा एप पर अनिवार्य रूप से देनी होगी।

★ पीएमएफबीवाय (PMFBY) फसल बीमा, अब फसल बीमा ऐप पर भी उपलब्ध है और स्थानीय आपदा के मामले में, बीमित किसान फसल बीमा ऐप का उपयोग करके अपनी फसल के नुकसान की सूचना भी दे सकते हैं।

योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें

इफको-टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

प्रधान कार्यालय: इफको टॉवर II, प्लॉट नं.-3, सेक्टर-29, गुरुग्राम (हरियाणा)- 122001

वेबसाइट : www.iffcotokio.co.in | ई-मेल : supportagri@iffcotokio.co.in

➢ कृषि बीमा हेतु अधिक जानकारी के लिए भारत सरकार द्वारा बनाये गये वेब पोर्टल www,pmfby.gov.in, कृषि/उद्यान विभाग, कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन, PMFBY प्रचालन मार्गदर्शिका का संदर्भ लें। ➢ बीमा आग्रह की विषय वस्तु है। ➢ जोखिम कारकों, नियमों और शर्तो के बारे में अधिक जानकारी के लिए, बिक्री समापन से पहले कृपया बिक्री विवरणिका को ध्यान से पढ़ें।

IRDAI Regd. No.106 | CIN: U74899DL2000PLC107621 | UAN: IFFCOTOKIO/25-26/InsAdvt/Rural-39